(7) इस तथ्य के अनुसार वैधानिक नियम प्रदान करते हैं रुपये का पे - स्कैन। फुल एनालिटिक्स के पद पर 5500-9000, द उत्तरदाता इसके विपरीत रुख अपना नहीं सकता है और एक्जीक्यूटिव नियुक्त के माध्यम से उक्त पद के वेतन - बड़े पैमाने पर रु . 5450-8000. क्रिया उत्तरदाता , इस प्रकार , निरंतर और लागू आदेश दिनांक 7 अगस्त , 2006 (अनुबंध पी -5) को नहीं दिया जा सकता है । 2, निरंतर नहीं किया जा सकता है .

(8) उल्लेखित के अनुसार , इस रिट याचिका की प्रतिलिपि 7 अगस्त , 2006 (अनुलग्नक पी -5) को दी गई है, जिसे रद्द कर दिया गया है ।

फ़तेब से पहले एस . गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह , जे जे ।

रमणिक कुमार और *अन्य, ग्रोथ बनाम*

हरियाणा

की स्थिति , *उत्तरदाता सीडब्ल्यूपी*

2007 की संख्या 13 709

31 अक्टूबर , 2008

भारत का संविधान , 1950 - कला । 226 • पंजाब पुलिस नियम , 1934 — री . 12.18 - निर्देश दिनांक 2 जुलाई , 2007 और 13 नवंबर , 2007 को राज्य स्तर पर प्रवेश हरियाणा - गैर कॉन्स्टेबल के रूप में 13 नवंबर , 2007 के लिए गैर कॉन्स्टेबल के खिलाफ विचार - सीएल 2 (ए) मंजूरी के लिए वह बहस प्रदान करता है कॉन्स्टेबुलरी नंबर उन लोगों पर लागू होगा जो जांच / परीक्षण या शामिल अपराध का सामना कर रहे हैं नैतिक नैतिकता केवल - जातिवाद के मामलों को पूरी तरह से कवर किया गया 13 नवंबर , 2007 के का पैरा 2 (ए) - डीबेर के लिए कॉन्स्टेबुलरी नंबर का विवरण नहीं दिया जा सकता है - उत्तरदाताओं की कार्रवाई आरएल 12.18 के विपरीत और साथ ही 13 तारीख के निर्देश नवंबर , 2007 - दस्तावेजों ने जारी किए कांस्टेबुलरी नंबर दर्ज किया गया ।

एच एल्ड , वह , *वीडियो* निर्देश दिनांक 13 नवंबर , 2007 पैरा 2 जुलाई , 2007 के उद्घाटन के 2 खंड (बी) को स्पष्ट कर दिया गया / शुरू हुआ इस खंड में सभी प्रतिभावानों के विचारों के बारे में पूरी तरह से विचार किया गया है रोक दिया गया , जो परीक्षण के लिए सामना कर रहे थे वह कोई भी आपराधिक अपराध था । उत्तरदाताओं ने 2 जुलाई , 2007 को इस पैरा 2 क्लॉज (बी) पर विश्वसनीय निर्देश दिए , जो उनके अनुसार स्टैंड है , स्पष्ट किया गया है , - 13 नवंबर , 2007 को विस्तृत निर्देश । उत्तरदाता ने गलत तरीके से 2 जुलाई, 2007 को दिए गए निर्देशों को लागू किया है , 13 नवंबर को निर्देश दिए गए हैं कि 2007, 2007, 2 जुलाई , 2007 को दिए गए निर्देशों में पैरा 2 (ए) मामले में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया जाए। इस मामले में लागू होता है कि राहुल गांधी को पूरी तरह से कवर किया गया है और इसलिए , उत्पाद कर रहे हैं कॉन्स्टेबुलरी नंबर के लिए चिह्नित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे कॉन्स्टेबलों के प्रतिष्ठा के लिए स्पष्ट उम्मीदवार थे । पंजाब पुलिस के अधिकारियों की कार्रवाई में 12.18 के विपरीत लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, उनकी मान्यता की तारीख 13 नवंबर , 2007 है और इसलिए , निरंतरता जारी नहीं रखी जा सकती है । उद्योगों के प्रकाश में कांस्टेबुलरी संख्या के अंकित व्यक्तियों के नाम शामिल हैं - जिन पर वे लागू होते हैं - जिन पर वे लागू होते हैं - जिन पर वे लागू होते हैं - जिन पर वे लागू होते हैं - जिन पर वे लागू होते हैं, उन्हें भी पुलिस द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

(पैरा 13)

विक्रम सिंह , एडवोकेट , के लिए *बजाज*.

ऋषि राठे , *सीनियर / DAQ हरियाणा /*

एक अगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे /

(1) यहां के पेट्रोलियम पुलिस विभाग में हरियाणा में कांस्टेबल्स (जीडी) के उम्मीदवारों को चुना गया है और आरोप लगाया गया है कि उनके चयन के बावजूद , उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई है । उनका विवाद है कि हरियाणा राज्य ने 2 मई , 2006 को कॉन्स्टेबल्स (जीडी) के 3700 पोस्टर्स का विज्ञापन किया था । अंतिम तिथि विज्ञापन के लिए आवेदन जमा करना , 24 मई , 2006 और इसके बाद , दोनों मित्रों ने अपनी याचिका प्रस्तुत की । उन्होंने शारीरिक परीक्षण परीक्षण और साक्षात्कार को मंजूरी दे दी

उक्त परीक्षण और उनकी प्रतिभाओं का चयन सूची में अप्रैल , 2007 के महीने में जिले के सामान्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे काउंसिल्स (जीडी) के रूप में करनाल में प्रकाशित किया गया था । प्रोडक्ट नंबर 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर 1033 था और प्रोडक्ट नंबर 2 का नंबर 46 था . इसके बाद उत्पादों को चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स को मंजूरी दे दी गई थी और अंततः उत्पादों का नाम नीचे दिए गए चरित्र सत्यापन के लिए भेजा गया था । कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित कॉन्स्टेबल्स (जीडी) के रूप में , जो उत्पादों के लिए योग्यता में कम थे , उन्हें कॉन्स्टेबुलरी नंबर से सम्मानित किया गया और नौ के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित आधार पर भेजा गया । कंपनियों को न तो कांस्टेबुलरी नंबर के साथ सम्मानित किया गया और न ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था । जांच पर , दर्शकों को पर्यवेक्षक के कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से पुलिस के जनरल को सूचित किया गया था कि उनके खिलाफ दर्ज परीक्षण मामले हैं , जो आराम कर रहे हैं , इसलिए , उनके पास कोई संख्या नहीं हो सकती है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए चित्रित नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है .

(2) सब्जियों का तर्क है कि पंजाब पुलिस के नियम 12 । नियम का 1 , जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू होता है और दिनांक 18 जून , 2002 को घोषित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि एक उम्मीदवार , जिसे किसी भी अपराध के लिए किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है , नैतिक विध्वंस के तहत , जैसा कि सरकार के निर्देशों को नष्ट कर दिया गया है

समय - समय पर , केवल ढांचे के तहत संवैधानिक रूप से समर्थक के रूप में विचार किया जाता है । जैसा कि कंपनियों के साथ संबंध है , उन्हें कॉन्स्टेबल्स के रूप में केवल निर्माताओं के खिलाफ नहीं माना जाता है और उन्होंने सभी पदों और साक्षात्कारों के बाद एक राय व्यक्त की है , क्योंकि उनके सहयोगियों के संबंध पूरे हो गए हैं । बिक्री संख्या 1 का कहना है कि रजिस्ट्री संख्या 606 दिनांक 23 वाँ नवंबर , 2006 धारा 148, 149, 323, 324 और 506 रजिस्ट्री के तहत , पुलिस स्टेशन सिटी स्टेट्सर पंजीकृत किया गया था , उसके खिलाफ धारा 307 बाद में जोड़ दी गई । उनका आगे का कहना है कि यह एक लड़ाई थी जो कॉलेज के छात्रों के बीच थी और जहां राघव का नाम नहीं बताया गया है , लेकिन उन्हें कोर्ट में एक छात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है । आयकर क्रमांक 2 में कहा गया है कि धारा 148, 149, 323, 324, 452 के साथ धारा 148, 149, 323, 324, 452 को धारा 39 दिनांकित किया गया है , पुलिस के अधीन ताराओरी को उनके खिलाफ पंजीकृत किया गया था , जिसके बाद धारा 307 को जोड़ा गया था . यह है विवाद का विषय यह है कि यह किराने का सामान बेच दिया गया था और बीच-बीच में दुश्मनी के कारण आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण उन्हें एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था । मामला पूरी तरह से गलत है या अचिकाकार्ता को बलि का बकरा बनाया गया है । आगे के विवाद में दोनों कंपनियों ने कहा है कि किसी भी अपराध के आरोप में कंपनियों के नैतिक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए , उन्हें हरियाणा राज्य के लिए लागू पंजाब पुलिस के लिए खारिज नहीं किया जा रहा है । यह विवाद यह है कि किसी भी मामले में , विभिन्न उत्पादों को दोष नहीं दिया जाता है , इसलिए कहा जाता है कि नैतिक नैतिकता से जुड़ा अपराध , उत्तरदाता उत्पादों को पुराने उत्पादों के तहत कॉन्स्टेबल उत्पादों से खारिज नहीं किया जा सकता है ।

(3) नोटिस जारी होने पर , उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों को उजागर किया है, उनके बारे में कोई विवाद नहीं है । उत्तरदाताओं द्वारा उनके

उत्तर में उठाए गए एकमात्र विवाद के अनुसार, यह पाया गया कि असमानता का मामला दर्ज नहीं किया गया था । मैं (रमणिक कुमार) अभी भी कुरुक्षेत्र में कोर्ट में था और बाथरूम के खिलाफ मामला दर्ज किया था । 2 (अरविंद राणा) अभी भी कमल की अदालत में था । यह उत्तरदाता का रुख है कि संबंध में , निर्देश 2 जुलाई , 2007 को पुलिस , हरियाणा द्वारा जारी किए गए आधार पर, यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि वे कहते हैं कि " वे सभी प्रतियोगी , जो किसी भी आपराधिक अपराधी का सामना कर रहे हैं , एक बार फिर विचार नहीं किया जाएगा कि किस तरह के वकील के रूप में ", इन अपॉइंटमेंट की प्रति है अनुलग्नक आर - आई के रूप में संलग्न । इसमें आगे प्रस्तुत किया गया है कि 31 वें दिनांक के निर्देशात्मक नैतिक मामले नवंबर , 2007 में नामांकित अनुलग्नक आर- II के रूप में जुड़े हुए हैं । इन दो अचल संपत्तियों में , उत्तरदाताओं का तर्क है कि उत्पादों को कॉन्स्टेबल्स के रूप में बेचा जा सकता है ।

(4) इस दस्तावेज़ के आवेदन के दौरान , दोनों उत्पाद , जो ऊपर उल्लिखित हैं, अपने संबंधित आवेदकों में परीक्षण का सामना कर रहे हैं , उनके पास दफन कर दिया गया है । रमणिक कुमार (संख्या 1) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा अपना निर्णय दिया गया , 2008 और अरविंद राणा (संख्या 2) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा अपना निर्णय दिया गया , - वीडियो 11 जून , 2008 को अतिरिक्त सत्रों को अपना निर्णय दिया गया, 2008 जज , करनाल । कंपनी ने उक्त निर्णयों को क्रमशः अनुलग्नक पी -4 एवं पी -3 के रूप में रिकार्ड कर रखा है । निर्णयों पर विश्वास करते हुए , विश्वासियों का तर्क है कि वे ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और निर्णयों की गड़बड़ी से पता चलता है कि कोई सबूत नहीं आया है

परीक्षण के दौरान , जो अभियोजन पक्ष का समर्थन कर सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड की गई सामग्री नहीं लाया गया है । अभियोजन पक्ष के आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में बुरी तरह से विफल रहा है और उनके लगाए गए आरोपों से बैर कर दिया गया है । कंपनी ने 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14028 में इस कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा करते हुए कहा कि **ललित कुमार** *बनाम* **राज्य हरियाणा और अन्य ने** 27 फरवरी , 2004 को निर्णय लिया कि वह चुनाव लड़ेगी केवल इसलिए कि समर्थकों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। संदेह का लाभ यह है कि इस स्टेरॉयड को कॉन्स्टेबल्स के इंजेक्शन के बिना किसी मामले में बार-बार नहीं लिया जाना चाहिए । वे आगे इस न्यायालय के एक अन्य डिवीजन बेंच के पर जजमेंट करते हैं, 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17043 में शीर्षक के रूप में **प्रदीप कुमार** *बनाम* **राज्य हरियाणा और अन्य** 2 मई , 2008 को इसके बाद चुनावी लड़ाई का फैसला आपराधिक मामलों में उनकी बारी में हुआ। होना , जिसमें नैतिकता शामिल नहीं है , स्केल को कांस्टेबल्स के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ।

(5) वेबसाइट पर आवेदकों के लिए और उनके साथ वकील को सहायता मामले के रिकॉर्ड के माध्यम से सुनवाई की जाती है ।

(6) पंजाब पुलिस के नियम 12.18 हरियाणा राज्य में लागू होते हैं , - वीडियो अधिसूचना दिनांक 18 जून , 2002 इस प्रकार है :

" नियम 12.18 वर्ण का अनुपालन करता है : —

इस विषय पर सरकार के अनुसार, कांस्टेबल के पद के लिए जांच विभाग के साथ एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट और चरित्र सत्यापन किया जाएगा । " जो उम्मीदवार किसी भी अपराध के तहत दोषी

ठहराया गया है, किसी भी कानून , नैतिक अपराध के तहत , जैसा कि समय - समय पर सरकारी निर्देश पर लागू होता है , इन नियमों के तहत कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया होगा ।"

(7) औसत नियमों के एक सिद्धांत में यह बताया गया है कि यह केवल किसी भी कानून के तहत किसी भी अपराध की सजा के लिए चल रहा है , जिसमें नैतिक असंतुलन शामिल है और समय - समय पर सरकारी तौर पर शामिल किया गया है , जो घटना के तहत विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

(() पुलिस महानिदेशक , हरियाणा द्वारा जारी निर्देश दिनांक 2 जुलाई , 2007 (अनुबंधक आर - I), जो इस प्रकार के मोर्टार के अंतर्गत है :-

" विषय : कांस्टेबुलरी वारंट का उम्मीदवार के पद के लिए लेटर ।

विवरण /

सेलेक्शन बोर्ड के कुछ अध्यक्षों ने मांग की है कि कांस्टेबल्स के पास स्थित अज्ञात स्थान में भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले और बाद में बरी कर दिया गया था ।

2. मामले की जांच हो गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि :-

(a) जो उम्मीदवार आपराधिक मामलों में शामिल थे और उन्होंने घोषणा की कि समय-समय पर बरी होने के बारे में पुष्टी के बारे में चयन सूची पर विचार किया जा सकता है, भले ही उन्होंने अपने सामना करने के परीक्षण या स्तम्भ में बरी होने के बारे में खुलासा नहीं किया हो । पत्र की संख्या 12. लेकिन वो जिन लोगों को नैतिक मूल्यों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने अपने परीक्षण में उथल-पुथल मचाई है, लेकिन केवल तकनीकी आधार पर या तकनीकी आधार पर संदेह के लाभ के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। . इस संबंध में यह कहा गया है कि सभी मामलों में नैतिक प्रतिबंध के बाद सूक्ष्मता

की जांच के सिद्धांत और इस तरह के दृष्टिकोण के अनुसार जिन बेंजामिन को सम्मान देना बंद कर दिया गया है, हालांकि , इस संबंध में विचार किया जा रहा है। कान्सुल हो सकता है .

(b) वे सभी प्रतियोगी जो किसी के लिए मोटरसाइकिल का सामना कर रहे हैं वे आपराधिक अपराधी के रूप में अपराधी के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

(c) जिन निर्दोष को किसी के लिए दोषी ठहराया गया है, उन्हें आपराधिक अपराध की पेशकश नहीं की जाएगी ।

( ) . . .,
(आर . एस . दलाल),
पुलिस महानिदेशक , हरियाणा ।"

रमणिक कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा का राज्य 897
और अन्य *(ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह , I)*

(9) इसके बाद कथित कुख्यात का सार्जेंट जारी किया गया , - *वीडियो* निर्देश दिनांक 13 नवंबर , 2007 (अनुलग्नक आरसीएडी , जो इस प्रकार है :

" सम्मेलन

इस कार्यालय के अंत में जारी है . नहीं . 7463-68/ ई (द्वितीय) मूल विषय पर 1, दिनांक 2 जुलाई 2007।

2. इस मामले की और जांच की गई है और स्पष्टता से गायब किया गया है , - इस कार्यालय पत्र के अनुसार विपक्ष के रूप में : -

(a) जिन आरोपियों के खिलाफ मामले में आरोपियों के खिलाफ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, जो उनका सामना कर रहे हैं, उन्हें ठीक से कांस्टेबुलरी नंबर जांच / परीक्षण या दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक नैतिकता शामिल है ।

(b) वैज्ञानिक आधार पर नैतिक शिक्षा से जुड़े अपराध पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

(c) अपील में दावा किया गया है कि पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा क्वेश्चन के रूप में फिट हो सकता है, कांस्टेबुलरी रिजर्व के लिए विचार किया गया है ।

के खिलाफ झील कांस्टेबुलरी भंडार को बंद करने की अनुमति दी जाती है ।

( ) . .

(आरएस दलाल)
पुलिस महानिदेशक , हरियाणा ।"

(10) 2 जुलाई , 2000 2007 को उगी जानकारी का एक अनुमान कि पुलिस , हरियाणा *था , - वीडियो* क्लॉज (बी) और (सी) में इन कहानियों ने सभी को निराश किया , किसी भी आपराधिक अपराध के विचार के लिए पूछताछ की गई के लिए दोषी ठहराए गए हैकल्स के रूप में मैसाचुसेट्स . यह स्थिति ऐसी अनोखी है कि डायरेक्टर पुलिस जनरल ने वैधानिक नियम 12.18 के विपरीत महसूस किया।

जे ऐसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है (अपडेट प्रस्तुत) और , इसलिए , स्थिति को स्पष्ट किया गया , - 13 नवंबर , 2007 को विस्तृत निर्देश । इन अधिसूचना के खंड (ए) का एक अनुमान यह है कि पहले 2 जुलाई , 2007 को इस अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया गया था कि कांस्टेबुलरी नंबर के लिए विशेष रूप से डिबारमेंट लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोगों को जांच / परीक्षण का सामना करना पड़ेगा । कर रहे हैं या केवल नैतिक नैतिकता से जुड़े अपराधियों में बरी हो गए हैं ।

(11) इस पैरा 10 में उत्पादों के खिलाफ सकारात्मक मामला दर्ज किया गया है जिसमें कहा गया है कि अवैध तरीके से उनके पंजीकृत ए *मैलामैरा* इंप्रेशन और अपराधशास्त्र में मनोवैज्ञानिक शामिल नहीं हैं । रिट पोस्टल के पैरा नंबर 10 के रूप में रेस्तरां इस प्रकार है : -

"10. अभिलेखों के अनुमान से , यह स्पष्ट है कि उत्पादों को गलत तरीके से शामिल किया गया है, जिसमें धार्मिकता और आक्षेप से संबंधित निर्दिष्ट मामले शामिल हैं, जिनमें कोई *नैतिक* मूल्य नहीं है। "

(12) कंपनियों का दावा है कि अपराध , जो बिल्डरों ने आरोप लगाए हैं , उनमें नैतिक मनोवैज्ञानिक शामिल नहीं हैं , उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में इसे खारिज कर दिया है । लिखित कथन का अनुच्छेद 10 : ---------- रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के अंतर्गत : -

"10. याचिका के पैरा नंबर 10 के उत्तर में , यह प्रस्तुत किया गया है कि इसमें शामिल दोनों उत्पाद आपराधिक मामले हैं और ये *दुर्भावनापूर्ण रूप* से पंजीकृत नहीं थे , उनके खिलाफ जो अभी भी अदालत में शामिल हैं, वे क्रमशः कुरुक्षेत्र और कर्णाल हैं ।"

(13) वास्तविक के वास्तविक , उत्पादों का मामला पूरी तरह से 13 नवंबर को दिया गया है, जो कि दिए गए उल्लिखित पैरा 2 क्लॉज (ए) के अंडर कवर , 2007 (अनुलग्नक आर - II), जो मामलों के रूप में पुलिस गोदाम , हरियाणा द्वारा जारी किया गया है। 2 जुलाई , 2007 को जारी किए गए दस्तावेज़ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आस्था के खिलाफ थे , वे अपराध से संबंधित थे , जिसमें नैतिक नैतिकता शामिल नहीं थी क्योंकि इसे ठीक नहीं किया गया था, उत्तरदाताओं ने अपनी लिखित बयान में कहा है । इस स्थान से बाहर यहां उल्लेख नहीं किया गया है कि , - *वीडियो* निर्देश दिनांक 13 नवंबर , 2007 पैरा 2 जुलाई , 2007 के उद्घाटन के 2 खंड (बी) को स्पष्ट किया गया / इंटरैक्टिव रूप में डिजाइन इस खंड ने पूरी तरह से विचार के लिए कहा रोकें

सभी बदमाशों के रूप में अपराधी , जो परीक्षण के लिए सामना कर रहे थे, वे भी कोई आपराधिक अपराध थे । उत्तरदाताओं ने इस पैरा 2 खंड को विश्वसनीय बताया है (बी) के लिए दिनांक 2 जुलाई , 2007 , जो उनके अनुसार है , स्पष्ट किया गया है , - 13 नवंबर , 2007 को विस्तृत निर्देश । गलत तरीके से 2 जुलाई , 2007 को उत्पादों के मामले में दिए गए निर्देशों को लागू किया गया है , 13 नवंबर को दिए गए निर्देशों में बताया गया है कि 2007 , 2007 में उत्पादों के मामले में दिए गए निर्देश गलत तरीके से लागू किए गए हैं । पैरा 2 (ए) में , उत्पादों का मामला पूरी तरह से कवर किया गया है और इसलिए , उत्पादों को नहीं कर सके कॉन्स्टेबुलरी संख्या के लिए विशिष्टताओं का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि वे पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे । पंजाब पुलिस के मानक 12.18 के अनुसार राज्य में 13 नवंबर , 2007 को लागू होने वाले उत्तरदाताओं की कार्रवाई के आंकड़ों के विपरीत, हरियाणा के साथ - साथ उनके निर्देश भी (अनुबंधक आर -11) और , इसलिए , निरंतर नहीं किया जा सकता . कंपनी के कांस्टेबुलरी में सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या में वामपंथी सिद्धांत लागू होते हैं, जिन्हें उनके पास नियुक्त किया गया है और पुलिस महानिदेशक के अधीन निदेशक द्वारा जारी किया गया है।

(14) जैसा कि हमने पहले से ही उत्पादों के लिए नामांकित किया है कांस्टेबुलरी नंबर का एबंटन , हमें ऐसा नहीं लगता है कि उत्पादों को अन्य उत्पादों द्वारा तय किया गया है ताकि आगे बढ़ने के लिए स्नातक न्यायालय द्वारा योग्यता न्यायालय द्वारा उनके पंजीकृत पंजीकरण के खिलाफ दावा किया जा सके। .

(15) उपयोगिता के प्रकाश में , इस रिट पत्र की मात्रा है . 15 दिनों की अवधि के भीतर इस ऑर्डर की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से कॉन्स्टेबल्स (जीडीई) के लिए प्रॉडक्ट्स को कॉन्स्टेबल नंबर देने के लिए निर्देशित किया जाता है । . उन्हें दिए जाएंगे उत्पादों के लिए योग्यता में कम हिस्सेदारी की तारीख से वरिष्ठता थी निवेश

कांस्टेबुलरी संख्या । वे डीएमडी के नामित होंगे वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ । हालाँकि , यह स्पष्ट है कि उन्हें बिना किसी लाभ के केवल साधारण लाभ मिलेगा, वास्तविक वित्तीय लाभ , ' कोई काम नहीं वेतन ' के सिद्धांत को देखा गया ' के मामले में फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है **" संघ का भारत और दूसरा** *बनाम* **तारसेम लाल और अन्य (1).**

आरएनआर

---

(1) 2006 (10) एस . सी . सी . 145

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी
(Trainee Judicial
Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़